



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2009/भाद्र 20, 1931

No. 522]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2009/BHADRA 20, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2009

सं. 98/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 664(अ)।—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, उन सामग्रियों को, जिनका आयात विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.2.1 और 4.2.2 की दृष्टि से जारी अग्रिम प्राधिकार (एतश्मन पश्चात् जिसे उक्त प्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रति भारत में किया गया हो, एतद्वारा, उस पर लगने वाले उस सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उस सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाठन शुल्क जो कि उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा क्रमशः 3, 8 ख और 9 के अंतर्गत लगाए गए हैं निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है यथा—

(i) यह कि आयातित सामग्री का विवरण, मूल्य और मात्रा कथित प्राधिकार से कवर हो तथा निकासी के समय कथित प्राधिकार को सीमा शुल्क के समुचित प्राधिकारी के समक्ष नामे करने के लिए प्रस्तुत किया जाए;

बशर्ते विदेश व्यापार नीति की क्रियाविधि पुस्तिका के पैराग्राफ 4.32.3 में विनिष्ट परिणामी उत्पादों के संदर्भ में, तत्काल आपूर्ति के लिए कथित प्राधिकार अथवा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार में अनुमत सामग्री उसी गुणवत्ता, तकनीकी प्रकृति और विनिर्देशन की होंगी, जैसा कि परिणामी उत्पाद में प्रयुक्त सामग्रियां होती हैं:

आगे शर्त यह है कि निर्यातक उपर्युक्त परिणामी उत्पाद के संदर्भ में नौप्रेषण बिल में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी प्रकृति और विनिर्देशनों के बारे में घोषणा पत्र देगा;

(ii) यह कि जहां आयात, निर्यात बाध्यताएं पूरी करने के बाद किया जाता है, कथित प्राधिकार में नौप्रेषण बिल संख्या और तारीख तथा मात्रा तथा परिणामी उत्पाद का फ्री आन बोर्ड मूल्य पृष्ठांकित किया जाए:

बशर्ते जहां आयात, निर्यात बाध्यताएं पूरी करने से पहले किया जाता है, कथित प्राधिकार पर निर्यात किए जाने वाले परिणामी उत्पाद की मात्रा और फ्री ऑन बोर्ड पृष्ठांकित किया जाए;

(iii) कि यदि आयात, निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह पूरा किये जाने के पहले किया जाता है तो आयातित सामग्री के लिए अनापत्ति लेते समय आयात कर्ता को उस जमानती या प्रत्याभूति का बंध पत्र उस रूप में तथा उस राशि का भरेगा जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके द्वारा वह लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, अपने को इस बात से वचनबद्ध करेगा कि वह उस आयातित सामग्री पर लगाये जाने वाले शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान कहे जाने पर कर देगा जिसके बारे में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, साथ ही साथ उक्त सामग्री की स्वीकृति की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा।

(iv) कि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह पूरा किये जाने के पश्चात् यदि आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर प्रदत्त शुल्क में छूट) या नियम 19 के उपनियम (2) अथवा सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के तहत सेनेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया जा चुका है, तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के लिए स्वीकृति लेते समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने की शुल्के योग्य माल के विनिर्माण में किया जायेगा और वह उक्त सामग्री की स्वीकृति मिलने की तारीख से 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है।

बशर्ते, यदि,

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित प्राधिकार के समक्ष सामग्री का आयात किया जाता है, अथवा

(ख) आयातित सामग्री का क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति से हस्तांतरण किया जाता है,

तो आयातकर्ता इस प्रकार आयातित या हस्तांतरित सामग्रीपर, इसमें शामिल छूट को छोड़कर, लगने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क की धनराशि के बराबर की धनराशि कथित सामग्री की निकासी की तारीख से पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित आदा करेगा:

आगे शर्त यह है कि 1.5.2006 से 31.3.2007 तक जारी प्राधिकारों के संदर्भ में ऐसी कोई धनराशि देय नहीं होगी:

आगे शर्त यह है कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर लगने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन उसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री

को इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी स्वीकृति को दिया जा सकता है और इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त सीमा शुल्क इयूटी पर वह सेनेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनेट क्रेडिट का लाभ पाने का पात्र होगा ।

(v) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है तो, और यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किये गये शुल्क पर छूट) और नियम 19 के अंतर्गत दी गई सुविधा और सेनेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनेट का लाभ नहीं लिया है तो और आयात कर्ता उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस बात का प्रमाण भी सौप देता है तो आयातित सामग्री को शर्त (iv) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(vi) यह कि आयात और निर्यात समुद्री बन्दरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बन्दरगाह का हल्दिया डॉक काम्पलेक्स) काकीनाडा, कोडला, कोलकाता, कृष्णापटनम, मगडाल्ला, मंगलौर, मारमगोवा, मुलद्वारका, मुम्बई, मुन्द्रा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपावव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टपम तथा वदिनार के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बत्तूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्रप्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भद्रोही, भटिंडा, भीलवाड़ा, भिवाडी, भुसावल, छेहाड़ता (अमृतसर), कोयम्बत्तूर, दादरी, डाप्पर (डेरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गढ़ी हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मलांपुर, मन्डीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाडी, रुद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर, तिरुपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतला, अमृतसर रेल कार्गी, अटारी रोड, चांगराबान्धा, डावकी, घोजाड़ंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सौनौतली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंधाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं ।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी

अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(vii) कि ऐसे परिणामी उत्पादों का निर्यात करके, जो कि भारत में विनिर्मित हो, जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हो, उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट निर्यात संबंधी दायित्वों को (मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से) उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर पूरा किया जाय जिसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमति प्रदान करें;

बशर्ते कि एडवान्स्ड इन्डरमीडिएट प्राधिकार धारक भी विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.3 (II) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात संबंधी दायित्वों को निभा सकता है;

(viii) कि आयातकर्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिये, दायित्वों को पूरा करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के साठ दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति प्रदान करें, प्रस्तुत करता है;

(ix) यह कि कथित प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात बाध्यताएं संपूर्ण रूप से पूरी होने से पहले छूट प्राप्त सामग्री का निर्यात बाध्यताएं पूरी करने के अतिरिक्त, किसी और तरीके से निस्तारण या प्रयोग नहीं किया जाएगा:

आगे शर्त यह है कि जहां कथित प्राधिकार के समक्ष शर्ते (iii) के अंतर्गत भरा गया बंधपत्र सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा उन्मोचित नहीं हैं, अप्रयुक्त सामग्री को जाब वर्क संबंधी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शर्त पूरी करने के बाद वास्तविक प्रयोक्ता दशा के अंतर्गत प्रसंस्करण हेतु अधिसूचना सं. 49/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 50/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों की तारीख 10 जून, 2003, 32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों का दिनांक 8 जुलाई, 1999, 8/04-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जनवरी, 2004, 20/07-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007, 56/02-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 57/02-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों का दिनांक 14 नवंबर, 2002, 71/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितम्बर, 2003, 56/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003 तथा 39/01-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001 का लाभ ले रही इकाइयों को छोड़कर, किसी और विनिर्माता को हस्तांतरित की जा सकती है;

(x) यह कि किसी निर्यातक को जारी, कथित प्राधिकार के संबंध में-

(क) यथा मामला शर्त संख्या (iii) या (iv) के निर्बंधनों के अनुसार निर्यातक द्वारा भरे जाने वाले बंधपत्र, जिसे व्यापारी निर्यातक तथा सहायक विनिर्माता दोनों संयुक्त रूप से और

भिन्न -भिन्न रूप से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करने के लिए भरते हैं, उसमें तथा कथित प्राधिकार में सहायक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाए, तथा (ख) छूट प्राप्त सामग्री का ऐसे सहायक विनिर्माता के कारखाने में निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए प्रयोग किया जाए तथा कथित व्यापारी निर्यातक द्वारा शर्त (vii) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता पूरी तरह पूरी होने से पहले हस्तांतरण, विक्रय या किसी और उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) पैराग्राफ 1 की शर्त (vii) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता पूरी होने के बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे प्राधिकार को और या उसके अंतर्गत आयातित माल को ऐसी शर्तों के अधीन हस्तांतरण की अनुमति देगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) जहां कि सामग्री दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पायी जाती है वहां उस सामग्री को स्वीकृति की तारीख से छह माह के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो छह माह से अधिक न हो जैसा आयुक्त सीमा शुल्क अनुमति प्रदान करें विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात किया जा सकता है।

बशर्ते ऐसी सामग्री के वापस निर्यात करते समय उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की संतुष्टि में यह पहचान हो कि यह वही सामग्री है जिसका कि आयात किया गया था ।

**स्पष्टीकरण:-** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(i) “शुल्केय माल” से अभिप्राय उस माल से है जिसपर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जिसे छूट प्राप्त नहीं है और जिस पर ‘शून्य’ दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(ii) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं.1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है।

(iii) “लाइसेंसिंग प्राधिकारी या क्षेत्रीय प्राधिकारी” से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22 से है) या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किये गये हों ।

(iv) “विनिर्माण” का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.37 में दिया गया है।

(v) “सामग्री” से अभिप्राय निम्न से है:-

(क) कच्चे माल, घटक, सहायक, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उसके भाग से हैं जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी होते हैं।

- (ख) मेन्डेटरी स्पेयर्स जो लाइसेंस मूल्य के 10% तक सीमित है और परिणामी उत्पादों के साथ-साथ जिसका आयात जरूरी होता है।
- (ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी ईधन
- (घ) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरूरी है।

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2009

**No. 98/2009-CUSTOMS**

**G.S.R. 664(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a Duty Free Import Authorisation issued in terms of paragraph 4.2.1 and 4.2.2 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under sections 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions namely :—

- (i) that the description, value and quantity of materials imported are covered by the said authorisation and the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit:

Provided that in respect of resultant product specified in paragraph 4.32.3 of the Hand Book of Procedures (Vol.I) of the Foreign Trade Policy, the materials permitted in the said authorisation or a duty free import authorisation for intermediate supply, as the case may be, shall be of the same quality, technical characteristics and specifications as the materials used in the said resultant product:

Provided further that in respect of the said resultant product the exporter shall give declaration with regard to the quality, technical characteristic and specifications of materials used in the shipping bill;

- (ii) that where import takes place after fulfilment of export obligation, the shipping bill number(s) and date(s) and quantity and Free on Board value of the resultant product are endorsed on the said authorisation:

Provided that where import takes place before fulfilment of export obligation, the quantity and Free on Board value of the resultant product to be exported are endorsed on the said authorisation;

- (iii) that in respect of imports made before the discharge of export obligation in full, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent. per annum from the date of clearance of the said materials;

(iv) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that, in case,

- (a) materials are imported against an authorisation transferred by the Regional Authority, or
- (b) the imported materials are transferred with the permission of Regional Authority,

then the importer shall pay an amount equal to the additional duty of customs leviable on the materials so imported or transferred, but for the exemption contained herein, together with interest at the rate of fifteen per cent. per annum from the date of clearance of the said materials:

Provided further that no such amount shall be payable in respect of Authorizations issued from 1.5.2006 to 31.3.2007:

Provided also that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2004;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule 2 of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (iv);

(vi) that the imports and exports are undertaken through seaports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Mormagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Puducherry, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthy (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi,

(Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanallur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jobani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may within the jurisdiction, by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permits import and export from any other seaport or airport or inland container depot or through any land customs station;

(vii) that the export obligation as specified in the said authorization (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorization or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorization;

Provided that an Advance Intermediate authorization holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to the exporter in terms of paragraph 4.1.3 (ii) of the Foreign Trade Policy;

(viii) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(ix) that exempt materials shall not be disposed of or utilised in any manner, except for utilisation in discharge of export obligation, before the export obligation under the said authorisation has been discharged in full;

Provided further that where the Bond filed under condition (iii) against the said authorisation has not been redeemed by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, the unutilised material may be transferred to any other manufacturer except to the unit availing the benefit of notifications, Nos. 49/03-CE and 50/03-CE both dated 10<sup>th</sup> June, 2003, 32/99-CE and 33/99-CE both dated 8<sup>th</sup> July, 1999, 8/04-CE dated 21<sup>st</sup> January, 2004, 20/07-CE dated 25<sup>th</sup> April, 2007, 56/02-CE and 57/02-CE both dated 14<sup>th</sup> November, 2002, 71/03-CE dated 9<sup>th</sup> September, 2003, 56/03-CE dated 25<sup>th</sup> June, 2003 and 39/01-CE dated 31<sup>st</sup> July, 2001, for processing under actual user condition after complying the central excise procedure relating to Job work;

(x) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter,-

(a) the name and address of the supporting manufacturer is specified in the said authorisation and the bond required to be executed by the importer in terms of condition numbers (iii) or (iv) as the case may be shall be executed jointly by the

merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification; and

(b) exempt materials are utilised in the factory of such supporting manufacturer for discharge of export obligation and the same shall not be transferred or sold or used for any other purpose by the said merchant exporter until the export obligation specified in condition (vii) has been discharged in full.

2. After discharge of export obligation as specified in condition (vii) of paragraph 1, the Regional Authority shall permit transfer of the said authorisation and/or the goods imported under it subject to such conditions as may be specified.

3. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said material or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow;

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

**Explanation – For the purposes of this notification,-**

(i) "Dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(ii) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1 /2009-2014, dated the 27th August 2009 as amended from time to time;

(iii) "Licensing Authority or Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence under the said Act;

(iv) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.37 of the Foreign Trade Policy;

(v) "Materials" means

- (a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;
- (b) mandatory spares within a value limit of ten per cent. of the value of the licence which are required to be exported along with the resultant product;
- (c) fuel required for manufacture of resultant product;
- (d) packaging materials required for packing of resultant product;

[F. No. 605/58/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.